समक्ष - हेमन्त गुप्ता जे.

जीवन मेहता - याचिकाकर्ता

बनाम

ईएमएम ब्रदर्स फोर्जिंग्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य - प्रतिवादी

C.A. No. 5 of 2008

2 नवंबर, 2010

कंपनी अधिनियम, 1956– धारा 397 और 398–अपीलकर्ता की जानकारी के बिना शेयर होल्डिंग के हस्तांतरण का आरोप–अपीलकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष समझौता ज्ञापन का उल्लेख करने में विफल रहा–बोर्ड ने तथ्यों को छिपाने और देरी और चूक के आधार पर याचिका खारिज कर दी–समझौता ज्ञापन का गैर-प्रकटीकरण–नहीं महत्वपूर्ण चूक जो अपीलकर्ता को योग्यता के आधार पर उसकी याचिका पर विचार करने से भी वंचित करती है - 1956 अधिनियम के 397 और 398 धारा के संदर्भ में बोर्ड का क्षेत्राधिकार। - वैधानिक- बोर्ड के याचिका को विचार योग्य न रखने का आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और कानून में टिकाऊ नहीं है- याचिका की अनुमति दी गई है, मामला कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर नए निर्णय के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया गया है।

अभिनिर्णित - हालांकि यह सवाल है कि क्या प्रतिवादी-कंपनी के मामलों को छूने वाला समझौता ज्ञापन प्रासंगिक है और किस हद तक बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे समझौता ज्ञापन का खुलासा न करना घातक है। ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है। क्या ऐसा समझौता ज्ञापन विचाराधीन कंपनी के लिए प्रासंगिक है और/या क्या मौखिक समझौता हुआ था या पार्टियों ने शेयरधारिता की अदला-बदली की है, समझौता ज्ञापन या समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कुछ प्रश्न होंगे, जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। सक्षम प्राधिकारी. लेकिन समझौता ज्ञापन का खुलासा न करना कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो विवाद की जड़ तक जाता हो और पक्षों के बीच सभी सवालों का फैसला न करता हो। इसलिए, भले ही अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में उक्त समझौता ज्ञापन का कोई संदर्भ नहीं दिया है, लेकिन यह कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं है, जो अपीलकर्ता को उसकी याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का भी अधिकार नहीं देता है।

(पैरा 23)

इसके अलावा, यह माना गया कि बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय इक्विटी की प्रसिद्ध कहावत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी करना चाहिए और जो इक्विटी में आता है उसे साफ हाथों से आना चाहिए, इसे तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। बोर्ड अधिनियम की धारा 397

और 398 के संदर्भ में वैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड, इक्विटी क्षेत्राधिकार का न्यायाधिकरण है। यह वैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

(पैरा 25)

अपीलकर्ता की ओर से अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव चोपड़ा और मुकुल अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से अरुण पल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, तुषार शर्मा, अधिवक्ता।

हेमन्त गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान में कंपनी लॉ बोर्ड, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित 20 नवंबर, 2007 के आदेश के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम') की धारा 10-एफ के तहत एक अपील है। बोर्ड') ने अधिनियम की धारा 402 और 403 के साथ पठित धारा 397 और 398 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(2) अपीलकर्ता ने कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 मेसर्स एम्म ब्रदर्स फोर्जिंग्स (पी) लिमिटेड, अधिनियम के तहत सीमित देयता वाली एक कंपनी है। कहा जाता है कि अपीलकर्ता के पास 67590 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर हैं, जो कुल चुकता शेयर पूंजी का 15.36%

है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को अपीलकर्ता के साथ निदेशक कहा जाता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 कंपनी का अध्यक्ष है। यह दलील दी गई है कि मेसर्स एम्म वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और उसके बाद, एक अन्य कंपनी एम्म ब्रदर्स मेटल्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1991 में हुई और प्रतिवादी-कंपनी की स्थापना वर्ष 1994 में हुई। 2000 से पहले प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार बताया गया है: -

क्र.सं.	**शेयरधारक का नाम**	**शेयर की संख्या**	**कुल चुकता शेयर पूंजी का %**
1	Jiwan Mehta	67590	15.36%
2	Ramesh Mehta	67580	15.36%
3	Raj Mehta	67580	15.36%.
4	Harish Mehta	67580	15.36%
5	Mohinder Mehta	67580	15.36% *
6	Ashok Mehta	67580	15.36%
7	Devi Rani Mehta	34500	7.84%
	Total	4,40,000	100%

(3) शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव आया है और उसके अनुसार 29 सितंबर, 2000 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**शेयरधारक का नाम**	**शेयर की संख्या**	**कुल चुकता शेयर पूंजी का %**
1	Jiwan Mehta	67590	15.36%
2	Ramesh Mehta	67580	15.36% ■
3	Raj Mehta	135170	30.72%
4	Mohinder Mehta	135170	30.72%
7	Devi Rani Mehta	34500	7.84%
	Total	4,40,000	100%

(4) उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि श्री हरीश मेहता और अशोक मेहता ने अपने शेयर श्री राज मेहता और श्री मोहिंदर मेहता के पक्ष में स्थानांतरित कर दिए हैं। यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी नंबर 3 श्री मोहिंदर मेहता को 7 जुलाई, 2000 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरदाता नंबर 2, 3 और 4 ने सहयोगी कंपनियों एम्म ब्रोज़ फोर्जिंग प्राइवेट में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी की अदला-बदली

की थी। लिमिटेड और एम्म ब्रोस मेटल्स प्रा. अपीलकर्ता की जानकारी के बिना लिमिटेड। इस तरह की अदला-बदली के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नंबर 2 और 3 एम्म ब्रोज़ फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड में बहुसंख्यक शेयरधारक बन गए हैं। लिमिटेड और एम्म ब्रोस मेटल प्रा. लिमिटेड अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि शेयर होल्डिंग का ऐसा हस्तांतरण अवैध है और प्रतिवादी-कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 7 और 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने 27 जनवरी, 2001 को अपीलकर्ता को बिना किसी सूचना के निदेशक पद से हटा दिया और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने 15 नवंबर, 2001 को 8वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी-अपनी पत्नियों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। 31 अगस्त, 2002 को कंपनी की हिस्सेदारी आयोजित की गई और उनके और उनकी पत्नियों के नाम पर शेयर पूंजी जुटाई गई ताकि शेष सभी शेयरधारकों के मुकाबले बहुमत हिस्सेदारी हासिल की जा सके।

(5) यह आरोप लगाया गया है कि मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रतिवादी-कंपनी का वार्षिक रिटर्न अपीलकर्ता के नकली हस्ताक्षर के बाद दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता ने अपने हस्ताक्षरों को प्रतिष्ठित फोरेंसिक विशेषज्ञ से सत्यापित कराया है, जिसकी रिपोर्ट अनुबंध ए.6 के रूप में संलग्न की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी-कंपनी द्वारा कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है, लेकिन अधिनियम की धारा 283(1)(जी) का सहारा लेकर अपीलकर्ता को प्रतिवादी-कंपनी के निदेशक पद से हटा दिया गया है। यह भी आरोप लगाया

गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 साझेदारी फर्म भी चला रहा था और उसने शेयर खरीदने और एम्म ब्रोस मेटल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए सभी फंडों को अपनी मालिकाना कंपनी में लगा दिया।

(6) अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त तथ्य पर, अपीलकर्ता ने कंपनी में शेयर होल्डिंग की बहाली की मांग की, जैसा कि वर्ष 2000 में किए गए हस्तांतरण से पहले मौजूद था और प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को धन बहाल करने और प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी के वित्तीय मामलों के खाते इस घोषणा के अलावा कि धन का उपयोग कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रतिवादी नंबर 2, 3 और 4 द्वारा अवैध रूप से किया गया था।

(7) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपीलकर्ता द्वारा दायर ऐसी याचिका का जवाब दायर किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि अपीलकर्ता साफ हाथों से अदालत में नहीं आया है। अपीलकर्ता ने अपीलकर्ता और उसके भाइयों के बीच हुए पारिवारिक समझौते को छुपाया और दबाया है, जो समझौता ज्ञापन से स्पष्ट है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने याचिका में अस्पष्ट और अनिश्चित दलीलें दी हैं और उत्पीड़न को उचित ठहराने के लिए यह आरोप नहीं लगाया है कि प्रतिवादी-कंपनी के बहुमत शेयरधारकों के कृत्य कठोर और गलत थे। यह बताया गया है कि व्यावसायिक फर्मों में श्री टी.डी. मेहता (पिता) और उनके छह बेटे यानी सर्वश्री जीवन मेहता, रमेश मेहता, राज मेहता, हरीश मेहता, मोहिंदर मेहता और अशोक मेहता शामिल थे। परिवार के मुखिया होने के नाते श्री टी.डी. मेहता

परिवार के तीन व्यवसायों, अर्थात् दो ईंट भट्टे और एक आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की देखरेख करते थे, जिसमें सभी छह बेटे या तो स्वयं या अपनी पत्नियों के माध्यम से भागीदार थे। परिवार की वृद्धि को देखते हुए श्री टी.डी.मेहता ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि पुत्रों को स्वतंत्र रूप से घर बसाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा परिवार होने के कारण यह केवल चरणों में और सहायक तरीके से ही संभव था। वर्ष 1989 में पंजाब से बाहर फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसलिए, मेसर्स एल्को टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली से एक रुग्ण इकाई। लिमिटेड (बाद में इसे एम्म ब्रोस'वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड में बदल दिया गया) के पास प्लॉट नंबर 6 और 7, सेक्टर 5, परवाणू (हिमाचल प्रदेश) में औद्योगिक भूमि और भवन था, जिसे अपने कब्जे में ले लिया गया और इमारत के नवीनीकरण के बाद, विनिर्माण के लिए एक इकाई बनाई गई। सुपर एनामेल्ड तांबे का तार लगाया गया। इसके बाद, वर्ष 1991 में, श्री टी.डी. मेहता ने परवाणू में एक और इकाई खरीदी और इसे मैसर्स एम्म ब्रोस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली के तहत स्थापित किया। लिमिटेड श्री टी. डी. मेहता और उनके बेटों के पास उक्त कंपनी में बराबर शेयर थे। लेकिन इस बात पर सहमति हुई कि कंपनी का नियंत्रण श्री हरीश मेहता और श्री अशोक मेहता द्वारा किया जाएगा। सभी छह बेटों और श्री टी. डी. मेहता के हिस्से बराबर थे। हालाँकि, अपीलकर्ता और श्री रमेश मेहता ने एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड में 68.5% शेयरों को नियंत्रित किया और उक्त कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन में हैं। वर्ष 1994 में, प्रतिवादी-कंपनी को श्री टी.डी.

मेहता के स्पष्ट निर्देश के साथ निगमित किया गया था कि ऐसी कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया है कि तीनों कंपनियों का कारोबार दो भाइयों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया गया था, हालांकि सभी छह भाइयों के पास तीनों कंपनियों में से प्रत्येक में शेयर थे।

(8) यह आगे दलील दी गई है कि वर्ष 1996 में श्री टी. डी. मेहता की मृत्यु के बाद, एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड के मामले, श्री जीवन मेहता द्वारा धन की भारी हेराफेरी के कारण खराब हो गए, एम्म से अपील 1 चींटी ब्रदर्स वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड। भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त कंपनी के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की। लिखित बयान में यह निवेदन किया गया है :-

> “6. वर्ष 1996 में स्वर्गीय श्री टी. डी. मेहता की मृत्यु के बाद, एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड से श्री जीवन मेहता द्वारा भारी मात्रा में धन की हेराफेरी के कारण कंपनी एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड के मामले बिगड़ गए। भारतीय स्टेट बैंक, परवाणु ने उक्त कंपनी के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही दायर की और याचिकाकर्ता के भाइयों द्वारा गारंटी के रूप में दी गई संपत्तियों को नीलाम करने की धमकी दी। इसलिए उनके बीच सभी मुद्दों को हल करने के लिए सभी छह भाई औपचारिक रूप से पारिवारिक संपत्ति और मेसर्स एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की संपत्ति और देनदारियों को विभाजित करने पर सहमत हुए। इसके बाद 7 अक्टूबर, 2001 को या उसके आसपास,

स्वर्गीय टी. डी. मेहता के सभी छह बेटों ने 7 अक्टूबर, 2001 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक आर 1 के रूप में चिह्नित है।

7. उक्त समझौते के संदर्भ में आपसी सहमति बनी याचिकाकर्ता और उत्तरदाता 2 से 4 कि पहली प्रतिवादी- कंपनी विशेष रूप से उत्तरदाताओं 2 और 3 की होगी और मेसर्स एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड विशेष रूप से याचिकाकर्ता और श्री रमेश मेहता और मेसर्स एम्म बॉस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड का होगा। लिमिटेड, विशेष रूप से हरीश मेहता और अशोक मेहता की होगी। उक्त समझौते में आगे यह सहमति हुई कि समायोजन के माध्यम से उपरोक्त कंपनियों में भाइयों के बीच सभी शेयरों/जमा/निवेशों से एक-दूसरे को मुक्त करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

8. 7 अक्टूबर, 2001 के समझौता ज्ञापन के संदर्भ में भाइयों के बीच उपरोक्त समझ से पहले, 21 जून, 2000 को प्रतिवादी संख्या 4 ने पहले प्रतिवादी के 33,000 इक्विटी शेयरों को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इसी प्रकार 21 जून, 2000 को श्री हरीश मेहता ने अपने 34,480 शेयर किसके पक्ष में हस्तांतरित किये?

प्रतिवादी संख्या 2। जब उपरोक्त स्थानान्तरण हुआ, तो याचिकाकर्ता प्रथम प्रतिवादी-कंपनी का निदेशक था और उक्त स्थानान्तरण के बारे में जानता था। इसके साथ ही उत्तरदाताओं 2 और 3 ने भी एम्म ब्रोस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने शेयर श्री अशोक मेहता और हरीश मेहता को हस्तांतरित कर दिए।

XXXXXX

10. 7 अक्टूबर, 2001 के उपर्युक्त समझौता ज्ञापन की अगली कड़ी, 2 जुलाई, 2002 को या उसके आसपास श्री रमेश मेहता ने पहली प्रतिवादी- कंपनी में 27,750 शेयर प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हस्तांतरित कर दिए। श्री रमेश मेहता ने उसी दिन यानी 2 जुलाई, 2002 को पहली प्रतिवादी-कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी प्रतिवादी नंबर 3 के पक्ष में स्थानांतरित कर दी। इसी तरह प्रतिवादी नंबर 2 ने एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स में अपनी पूरी शेयर हिस्सेदारी श्री रमेश मेहता के पक्ष में स्थानांतरित कर दी।

(9) उत्तरदाताओं ने 27 जुलाई, 2000 और 27 जनवरी, 2001 के निदेशक मंडल के प्रस्तावों पर भी भरोसा किया है, जिसके तहत प्रतिवादी-कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारिता के हस्तांतरण को स्वीकार कर लिया गया है। उत्तरदाताओं का यह स्पष्ट रुख है कि अन्य पांच भाइयों ने अपनी-अपनी कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन पाने के लिए प्रत्येक कंपनी में अपने-अपने शेयरों की अदला-बदली की है। हालाँकि, अपीलकर्ता ने कुछ गुप्त उद्देश्यों के लिए समझौता ज्ञापन की शर्तों का सम्मान नहीं किया है और पहले प्रतिवादी-कंपनी में शेयर होल्डिंग को दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के पक्ष में और एम्म ब्रोस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित नहीं किया है। लिमिटेड प्रतिवादी नंबर 4 और श्री हरीश मेहता के पक्ष में।

(10) उत्तर के पैरा 8.2 (बी) में, यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त शेयरों के हस्तांतरण के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2001 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और आपसी

समझौते के अनुसार, तीन कंपनियों को विभाजित किया गया था भाइयों के बीच. यह भी दलील दी गई कि रमेश मेहता, जिन्हें एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड का नियंत्रण और प्रबंधन करना था, ने पहले प्रतिवादी के शेयरों को प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है।

(11) यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने बोर्ड के समक्ष दायर लिखित बयान में वर्ष 1997 या वर्ष 2000 में पार्टियों के बीच हुए किसी मौखिक समझौते का उल्लेख किया है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया है कि वास्तव में, एम्म ब्रोस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका (2004 का सीपी नंबर 82) में ऐसे दावे किए गए हैं। लिमिटेड। उक्त याचिका पर बोर्ड द्वारा एक ही तारीख के अलग-अलग आदेश द्वारा एक साथ निर्णय लिया गया।

(12) विद्वान बोर्ड ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को मुख्य रूप से इस कारण से खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता ने याचिका की स्थिरता के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का खंडन करने की पेशकश नहीं की है। एक निष्कर्ष लौटाया गया है कि अपीलकर्ता को छोड़कर आवंटन, अदला-बदली आदि 27 जुलाई को मौखिक समझ के अनुसार किया गया था। 2000 और अपीलकर्ता ने जानबूझकर बोर्ड से समझौता ज्ञापन छुपाया है। हालाँकि यह माना गया कि न तो अपीलकर्ता और न ही प्रतिवादी मई, 2000 में सभी भाइयों के बीच आपसी सहमति से हुए मौखिक समझौते पर भरोसा करना चाहते हैं और बाद में 7

अक्टूबर, 2001 को इसे लिखित रूप में बदल दिया गया और उक्त समझौता ज्ञापन को रखा जाना था। समझौते के पूरा न होने और एप 11 एंट्स के शेयरों की अदला-बदली न होने के कारण यह स्थगित है। यह माना गया कि उत्तरदाताओं के आरोप कि अपीलकर्ता साफ हाथों से अदालत में नहीं आया है, सच साबित हुआ है और अपीलकर्ता हेराफेरी का दोषी है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला बोर्ड इक्विटी की प्रसिद्ध कहावत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी करना होगा। इसके अलावा, बोर्ड ने माना कि याचिका में देरी और देरी हो रही है क्योंकि शेयरों की अदला-बदली 25 जुलाई को की गई थी। 2000 और अपीलकर्ता को 27 जनवरी, 2001 को अपना कार्यालय खाली करने के लिए समझा गया, लेकिन याचिका केवल 31 अगस्त को दायर की गई थी। 2004. इसलिए, भले ही सीमा के प्रावधान लागू न हों, कार्यवाही में देरी और देरी होती है। यह माना गया कि आवंटन और अदला-बदली के अलावा, कार्यालय की छुट्टी अपीलकर्ता की पूरी जानकारी, सहमति/स्वीकृति के साथ थी, इसलिए वह पिछले और संपन्न लेनदेन को चुनौती नहीं दे सकता। इसे निम्नलिखित प्रभाव से आयोजित किया गया:-

> "इसके अलावा, कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष कार्यवाही शुरू करने में याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी और देरी को माफ करने की कोई दलील नहीं है। इसके अलावा, आवंटन, अदला-बदली, कार्यालय खाली करना याचिकाकर्ता की पूरी जानकारी, सहमति/स्वीकृति के साथ था। जो पिछले और संपन्न लेन-देन को चुनौती नहीं दे सकते। रोक, छूट और स्वीकृति

के सिद्धांत भी इस मामले में लागू होते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने उन्हें निदेशक के रूप में हटाने के संबंध में एक आरोप लगाया है। लेकिन याचिका में इस प्रार्थना में निदेशक के रूप में उनकी बहाली की मांग करने वाली कोई भी प्रार्थना शामिल नहीं है। प्रतिवादी-कंपनी।

उपरोक्त के आलोक में याचिका पोषणीय नहीं है। मुझे गुण-दोष के आधार पर तर्कों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं लगता। याचिका एतद्द्वारा खारिज की जाती है। सभी अंतरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। सभी सीए का निस्तारण किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

(13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि बोर्ड ने कथित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में विरोधाभासी निष्कर्ष दिए हैं। यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब बोर्ड ने स्वयं पाया कि समझौता ज्ञापन को प्रभावी नहीं किया गया था, तो बोर्ड को योग्यता के आधार पर याचिका पर विचार नहीं करने और यह निष्कर्ष देने में उचित नहीं था कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलकर्ता नहीं आया है। साफ हाथों से बोर्ड को। यह तर्क दिया गया है कि समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की पारिवारिक संपत्तियों और संपत्तियों और देनदारियों के संबंध में था, हालांकि क्लॉज (IV) के अनुसार, तीन कंपनियों का स्वामित्व दो के पास था। प्रत्येक भाई. यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुसार किसी भी पूर्व शर्त का सम्मान नहीं किया गया

था। इसलिए, ऐसे समझौता ज्ञापन का खुलासा न करना याचिका को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि समझौता ज्ञापन को प्रभावी नहीं किया गया था, सिविल रिट याचिका संख्या 3 765 ऑफ 2004 में प्रतिवादी नंबर 2 से 4 द्वारा दायर एक आवेदन (सीएम नंबर 5080 ऑफ 2004) से स्पष्ट है, जिसमें उसने कहा है निम्नानुसार बताया गया है:-

"जीवन मेहता याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छुपाया है कि यद्यपि एक पारिवारिक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार, उसमें उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, उक्त घर उसके व्यक्तिगत स्वतंत्र हिस्से में आना था, फिर भी उक्त पारिवारिक समझौता बना रहा वर्तमान आवेदकों को विभिन्न राशियों के भुगतान के माध्यम से उक्त समझौते में जीवन मेहता द्वारा अपने हिस्से की पूर्ति न करने और अन्य दायित्वों को पूरा न करने के कारण यह स्थगित है। इसलिए, जी वान मेहता ने जानबूझकर छुपाया है और पारिवारिक समझौते को रिकॉर्ड मेंनहीं रखा है। इसकी एक प्रति इस आवेदन के साथ अनुबंध ए के रूप में संलग्न है। यह दोहराया गया है कि उनके पारिवारिक समझौते पर कार्रवाई नहीं की गई और मकान नंबर 939, सेक्टर 8, पंचकुला जी वान मेहता और अशोक मेहता के स्वामित्व में बना हुआ है, जो उक्त घर के बराबर शेयरों के मालिक हैं।"

(14) यह तर्क दिया गया है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार, मकान नंबर 939, सेक्टर 8. पंचकुला का स्वामित्व विशेष रूप से अपीलकर्ता के पास था और रुपये की राशि थी। अपीलकर्ता द्वारा श्री रमेश मेहता को 10 लाख रुपये का भुगतान करना था और एम्म ब्रदर्स वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की सभी देनदारियों के पुनर्भुगतान के बाद, शेष नकदी प्रवाह को श्री जीवन मेहता और श्री रमेश मेहता द्वारा साझा किया जाना था। हालांकि ऐसी समझ थी, अशोक मेहता ने उक्त घर के विभाजन द्वारा अलग कब्जे का दावा करते हुए एक नागरिक मुकदमा दायर किया और कहा कि उक्त मुकदमा अभी भी लंबित है। 1 सितंबर के एक सार्वजनिक नोटिस (अनुलग्नक ए.7) का भी संदर्भ दिया गया है। 2001 में श्री रमेश मेहता और श्री अशोक मेहता द्वारा इस आशय से प्रकाशित किया गया कि एम्म ब्रदर्स वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से अपीलकर्ता को किसी भी बैंक खाते को संचालित करने और खोलने से रोक दिया गया है, हालांकि समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी श्री रमेश मेहता के साथ अपीलकर्ता द्वारा प्रबंधित किया जाना है। इस प्रकार, यह तर्क देने की कोशिश की गई है कि उक्त समझौते के किसी भी पक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन को प्रभावी नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि उक्त समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी विवाद और मतभेद से बचने के लिए सभी भाइयों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत मौखिक समझ को लिखित रूप में कम कर दिया गया है, जो मौखिक समझौते से संबंधित नहीं है। वर्ष 1997 या वर्ष 2000 में। उक्त समझौता ज्ञापन मौखिक समझौते की किसी विशेष तारीख

का उल्लेख नहीं करता है। वास्तव में, समझौता ज्ञापन के खंड (8) में उल्लिखित मौखिक समझौता 7 अक्टूबर को दस्तावेज़ को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने से ठीक पहले किए गए मौखिक समझौते के संबंध में है। 2001. अन्य भाइयों द्वारा शेयर होल्डिंग का हस्तांतरण यहां अपीलकर्ता सहित सभी के बीच किसी भी मौखिक समझ के अनुसरण में नहीं है।

(15) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि केवल अपीलकर्ता ही है, जिसने प्रतिवादी-कंपनी या एम्म ब्रोस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित नहीं की है। लिमिटेड की शेयरधारिता श्री रमेश मेहता द्वारा स्थानांतरित कर दी गई है, जिन्हें अपीलकर्ता के साथ संयुक्त रूप से मेसर्स एम्म ब्रदर्स वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड का स्वामित्व और प्रबंधन करना था। यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता एकमात्र भाई है, जिसने वर्ष 1997 और 2000 में हुए मौखिक समझौतों को प्रभावी नहीं किया है और इस तरह के समझौता ज्ञापन का खुलासा न करने को बोर्ड द्वारा अस्वीकार करने के लिए उचित रूप से विचार किया गया है।

(16) पार्टियों के विद्वान वकील के संबंधित तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से पहले, यह बताया जा सकता है कि चूंकि प्रतिवादी-कंपनी के निदेशक मंडल का संकल्प सुपाठ्य नहीं था; प्रतिवादी-कंपनी की मूल कार्यवाही पुस्तिका मंगाई गई। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त मिनट/कार्यवाही की फोटो प्रतियां भी पेश की हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति है।

(17) कार्यवाही पुस्तिका 7 जुलाई 2000 को आयोजित निदेशकों की बैठक से शुरू होती है, जिसमें यह तथ्य दर्ज है कि अपीलकर्ता बैठक से अनुपस्थित था और उसे कोई छुट्टी नहीं दी गई थी। बैठक का दूसरा मिनट 27 जुलाई, 2000 का है। अपीलकर्ता अनुपस्थित था और उसे छुट्टी नहीं दी गई थी, हालांकि श्री मोहिंदर मेहता को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई थी। मिनट में श्री अशोक मेहता और श्री हरीश मेहता के शेयरों के हस्तांतरण को रिकॉर्ड किया गया है। 23 अगस्त की बैठक में. 2000, अपीलकर्ता जीवन मेहता का नाम बैठक में उपस्थित व्यक्ति के रूप में उल्लेखित है, लेकिन कार्यवाही पुस्तिका पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। श्री मोहिंदर मेहता अनुपस्थित थे, लेकिन कोई छुट्टी नहीं दी गई थी। 17 अक्टूबर, 2000, 30 नवंबर, 2000, 30 दिसंबर, 2000 और 27 जनवरी, 2001 की बैठकों में, श्री अशोक मेहता और श्री राज मेहता बैठक में उपस्थित थे और अपीलकर्ता श्री जीवन मेहता को कोई अनुमति नहीं दी गई थी। छुट्टी। ऐसी बैठकों में मौजूदा व्यावसायिक कार्यक्रम या अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर चर्चा के अलावा कोई कामकाज नहीं हुआ है। 29 सितंबर, 2000 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में श्री मोहिन्दर मेहता और श्री राज मेहता के अलावा श्री जीवन मेहता के हस्ताक्षर हैं।

(18) कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत अपीलकर्ता द्वारा अपनी याचिका में समझौता ज्ञापन के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव पर ध्यान देने से पहले, मैंने प्रथम दृष्टया पाया कि कंपनी के वार्षिक रिटर्न पर उत्तरदाताओं की निर्भरता 29 सितंबर, 2000 को आयोजित

वार्षिक आम बैठक के अनुसरण में दायर किया गया, जिस पर बोर्ड ने भरोसा किया है, अपीलकर्ता के जाली और मनगढ़ंत हस्ताक्षरों पर आधारित है।

(19) प्रतिवादी संख्या 1 की 7 जुलाई 2000 से 27 जनवरी 2001 तक की कार्यवाही पुस्तिका से पता चलता है कि श्री जीवन मेहता बोर्ड बैठकों से अनुपस्थित हैं। यदि श्री जीवन मेहता 7 जुलाई, 2000 से बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, तो वह 29 सितंबर, 2000 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के अनुसरण में कंपनी के वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर कैसे करेंगे। यह असंभव लगता है। उक्त पहलू को फोरेंसिक विशेषज्ञ अनुबंध ए-6 की रिपोर्ट से समर्थन मिलता है, जिसमें ऐसे वार्षिक रिटर्न पर अपीलकर्ता जीवन मेहता के हस्ताक्षर जाली और मनगढ़ंत पाए गए हैं।

(20) उत्तरदाताओं ने कंपनी रजिस्ट्रार के संचार पर भी भरोसा किया है, जिसमें 27 जनवरी, 2001 को बोर्ड की बैठक में अपीलकर्ता द्वारा निदेशक के पद की समाप्ति के बारे में अपीलकर्ता को सूचित किया गया है। तीन बैठकें, जिनकी अनुपस्थिति के कारण अपीलकर्ता को कार्यालय खाली करना पड़ा, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर चर्चा हुई, जो 17 अक्टूबर, 2000, 30 नवंबर, 2000 और 30 दिसंबर, 2000 के कार्यवृत्त से स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा कार्यालय की समाप्ति के लिए आधार तैयार करने के लिए ऐसे कार्यवृत्त दर्ज किए गए हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया, तीन बोर्ड की बैठकों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर विचार में हेरफेर किया गया प्रतीत होता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर संभवतः बोर्ड

की तीन बैठकों में और कोई सुधारात्मक कदम उठाए बिना चर्चा नहीं की जा सकती। इस तरह के निष्कर्ष को प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ता की याचिका की पोषणीयता पर विचार करने के लिए दर्ज किया गया है। दस्तावेजों की विस्तृत जांच पर विचार करना और स्पष्ट निष्कर्ष देना सक्षम प्राधिकारी का काम है।

(21) बोर्ड ने माना है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर बोर्ड से समझौता ज्ञापन छुपाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, समझौता ज्ञापन परिवार को समान रूप से विभाजित करने के लिए है , एम्म ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की संपत्ति और संपत्ति और देनदारियां। प्रतिवादी-कंपनी की संपत्ति या शेयरधारिता समझौता ज्ञापन का विषय नहीं थी। प्रतिवादी-कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैं: -

> “यह समझौता ज्ञापन श्री जीवन मेहता, श्री रमेश मेहता, श्री राज मेहता, श्री हरीश मेहता, श्री मोहिंदर मेहता और श्री अशोक मेहता, स्वर्गीय श्री टी.डी. मेहता के सभी पुत्रों, सभी निवासियों, के बीच आज 7 अक्टूबर, 2001 को निष्पादित हुआ। पंचकुला, इसके द्वारा मैसर्स एम्म ब्रदर्स वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 6 और 7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर 5, परवाणू की पारिवारिक संपत्तियों और संपत्तियों और देनदारियों को औपचारिक रूप से विभाजित करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों, कार्यों और चीजों को निष्पादित करने पर सहमत हुआ। निम्नलिखित पर परस्पर सहमति हुई:-

1. मैसर्स एम्ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड का स्वामित्व और संचालन जीवन मेहता और रमेश मेहता के पास है और उन पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला का लगभग 25 लाख रुपये और भारतीय स्टेट बैंक, परवाणु शाखा का लगभग 160 लाख रुपये का ऋण बकाया है। लाख.

XX XX XX

10. मेसर्स एम्ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड की सभी देनदारियों के पुनर्भुगतान के बाद, शेष नकदी प्रवाह को जीवन मेहता और रमेश मेहता द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा, और इस एमओयू का कोई भी अन्य पक्ष अधिशेष साझा करने का हकदार नहीं है या घाटा।

XX XX XX

चतुर्थ. भाइयों के बीच आपसी समझौते के अनुसार, व्यवसायों का स्वामित्व निम्नानुसार होगा: -

मेसर्स एम्ब्रोस मेटल प्रा. लिमिटेड, परवाणू विशेष रूप से हरीश मेहता और अशोक मेहता का होगा।

मेसर्स एम्ब्रोस फोर्जिंग्स प्रा. लिमिटेड विशेष रूप से राज मेहता और मोहिंदर मेहता की होगी।

मेसर्स एम्ब्रोस वायर्स एंड स्ट्रिप्स। लिमिटेड, विशेष रूप से जीवन मेहता और रमेश मेहता का होगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसके अलावा किसी भी भाई का किसी भी कंपनी में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्यक्तिगत भाइयों को सभी संपत्तियों/भूखंडों को जारी करते समय, उपरोक्त उल्लिखित कंपनियों में भाइयों के बीच सभी शेयरों/जमा/निवेश से एक-दूसरे को राहत देने के लिए समायोजन के माध्यम से सभी प्रयास किए जाएंगे। और फर्मों एम/एसएमएक्सओवरसीज और एम्ब्रोसऑटोमोटिव में भी।

XX XX XX

VIII. भविष्य में किसी भी विवाद या मतभेद से बचने के लिए भाइयों के बीच आपसी सहमति से हुए मौखिक समझौते को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है।"

(22) समझौता ज्ञापन की कोई भी शर्त वर्ष 1997 या 2000 में कथित मौखिक समझौते का उल्लेख नहीं करती है, जिसका संदर्भ केवल बोर्ड द्वारा विवादित आदेश में किया गया है। किसी अन्य कंपनी के संबंध में अन्य मामलों में की गई दलीलों को वर्तमान याचिका में उठाए गए सवालों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। समझौता ज्ञापन के खंड-IV में दर्ज है कि "अब से, व्यवसायों का स्वामित्व निम्नानुसार होगा"। इससे यह पता नहीं चलता कि पहले कोई मौखिक समझौता हुआ था या दोनों पक्ष पहले ही किसी समझौते पर पहुंच चुके

हैं, जिसमें अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। व्यवसायों को समझौता ज्ञापन की तिथि से ही पुनर्गठित किया जाना था।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यह सवाल कि क्या प्रतिवादी-कंपनी के मामलों को छूने वाला समझौता ज्ञापन प्रासंगिक है और किस हद तक बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे ज्ञापन का खुलासा न किया जाए समझौता घातक है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिका स्वयं चलने योग्य नहीं है। क्या ऐसा समझौता ज्ञापन विचाराधीन कंपनी के लिए प्रासंगिक है और/या क्या मौखिक समझौता हुआ था या पार्टियों ने समझौता ज्ञापन के संदर्भ में शेयरधारिता की अदला-बदली की है?

समझौता ज्ञापन में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन समझौता ज्ञापन का खुलासा न करना कोई तथ्य नहीं है जो विवाद की जड़ तक जाता है और पक्षों के बीच सभी सवालों का निर्णायक रूप से निर्णय नहीं करता है। इसलिए, भले ही अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में उक्त समझौता ज्ञापन का कोई संदर्भ नहीं दिया है, लेकिन यह कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं है, जो अपीलकर्ता को उसकी याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का भी अधिकार नहीं देता है।

(24) प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने 2007 की कंपनी अपील संख्या 4 (2004 की कंपनी याचिका संख्या 82 में बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर) में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 6 जनवरी, 2010 के एक आदेश पर भी भरोसा किया है।) एम्म ब्रोस

मेटल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में। लिमिटेड, जिसमें बोर्ड के आदेश को बनाए रखा गया था। भले ही बोर्ड ने एक ही तारीख में दो याचिकाओं में आदेश पारित किया है, लेकिन दलीलें अलग-अलग हैं और वर्तमान मामले की दलीलों के आधार पर, मुझे लगता है कि विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।

(25) हालांकि पार्टियों के लिए विद्वान वकील ने तर्क नहीं दिया है, लेकिन बोर्ड द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय इक्विटी की प्रसिद्ध कहावत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी करना होगा और जो इक्विटी में आता है उसे साथ आना होगा साफ हाथ, टिकाऊ नहीं कहे जा सकते। बोर्ड अधिनियम की धारा 397 और 398 के संदर्भ में वैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड, इक्विटी क्षेत्राधिकार का न्यायाधिकरण है। यह वैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इस स्तर पर ऐसी खोज के संबंध में और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

(26) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि बोर्ड द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत यह माना गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है और कानून में कायम नहीं रह सकती है। परिणामस्वरूप, विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। मामले को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए बोर्ड के पास वापस भेज दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)